दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 || Postal Registration No-055/Raigarh DN CG || रायगढ़, शनिवार 05 जून 2021 || पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए || वर्ष-03, अंक- 245

महत्वपूर्ण एवं खास

काम की तलाश में नई उम्मीद लेकर लौट रहे प्रवासी मजदूर

नई दिल्ली (आरएनएस)। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के धीरे धीरे खत्म होने के साथ प्रवासी मजदूर काम की तलाश में एक बार फिर दिल्ली की ओर रुख कर रहें हैं। वहीं दिल्ली में अनलॉक प्रक्रिया के तहत इन सभी को फिर से जिंदगी पटरी पर लौटने की उम्मीद बनी हुई है। दिल्ली में निर्माण और फैक्ट्रियों को खोलने की इजाजत दिल्ली सरकार द्वारा दे दी गई है। आनंद विहार बस स्टैंड और कौशम्भी बस स्टैंड पर बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर बिहार , यूपी और अन्य राज्यों से एक बार फिर लौटने लगे हैं।

विश्व में कोरोना संक्रमितों की संख्या 17.20 करोड़ के पार

वाशिंगटन। विश्वभर में कोरोना वायरस (कोविड-19) का तांडव जारी है और अब तक इससे 17.20 करोड़ से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं जबकि 36.98 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। अमेरिका की जॉन हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी के विज्ञान एवं इंजीनियरिंग केंद्र (सीएसएसई) की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार दुनिया के 192 देशों एवं क्षेत्रों में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 17 करोड़ 20 लाख 21 हजार 452 हो गयी है, जबकि 36 लाख 98 हजार 538 लोगों की इस संक्रमण के कारण मौत हो चुकी है। विश्व में महाशक्ति माने जाने वाले अमेरिका में कोरोना वायरस की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ी है। हालांकि यहां संक्रमितों की संख्या तीन करोड़ 33 लाख 26 हजार 054 हो गयी है और करीब 5.96 लाख लोगों की इस संक्रमण से मौत हो गयी है।

यूपी में सभी सरकारी अस्पतालों में शुरू होंगी ओपीडी सेवाएं

लखनऊ (आरएनएस)। यूपी में कोरोना के घटते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 4 जून से प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवाओं को शुरू करने का ऐलान कर दिया है और कोरोना के अतिरिक्त अन्य बीमारियों से ग्रसित मरीजों की भर्ती करने और उनको समय से इलाज की सुविधाएं देने के आदेश दिए हैं। चिकित्सा विभाग के अधिकारी अस्पतालों में ओपीडी और आईपीडी सेवाओं की शुरुआत के साथ ही कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने की तैयारी में जुट गए हैं। मुख्यमंत्री के इस आदेश के बाद कोरोना के इतर अन्य बीमारियों से ग्रसित लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। सामान्य मरीज भी अस्पतालों में डॉक्टरों को दिखा सकेंगे। उचित परामर्श हासिल कर ऑपरेशन कराना उनके लिए आसान हो जाएगा। अस्पतालों में फैलते संक्रमण को देखते हुए जिन मरीजों की सर्जरी तीन महीने से रुकी हुई थी, अब उनकी सर्जरी भी पुनः हो सकेगी। इसके साथ ही फीवर ओपीडी, आई और ईएनटी ओपीडी, गाइनिक ओपीडी, सर्जरी ओपीडी से मरीजों को सेवाएं मिलेंगी। गर्भवती महिलाओं के साथ बच्चों को भी चिकित्सीय सुविधाएं मिलने से उनको राहत मिलेगी। यूपी में बेहतर हुई स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम-9 के अधिकारियों को आदेश दिए हैं। उन्होंने प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर कोविड प्रोटोकाल के साथ ओपीडी एवं आईपीडी सेवाएं 4 जून से शुरू करने को कहा है।

कोरोना संक्रमण के नए मामलों में मामूली गिरावट 24 घंटे में दर्ज हुए 1.32 लाख केस, 2713 की मौत

नई दिल्ली (आरएनएस)। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का पीक खत्म होने के बाद कोरोना मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। कोरोना के दैनिक मामलों में हल्की गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस के 1.32 लाख से कुछ ज्यादा मामले सामने आई। वहीं 2713 ने अपनी जान गंवाई है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक, देश में कोरोना वायरस के 1.32 लाख से ज्यादा दैनिक मामले दर्ज किए गए। जबकि इसी दौरान 2713 मरीजों की मौत हो गई। देश में अब तक कोरोना वायरस के कुल 2,85,74,350 संक्रमित मामले दर्ज किए जा चुके हैं। वहीं मृतकों की संख्या 3,40,702 हो गई है। देश में पिछले साल सात अगस्त को संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त को 30 लाख और पांच सितंबर को 40 लाख से अधिक हो गई थी। वहीं, संक्रमण के कुल मामले 16 सितंबर को 50 लाख, 28 सितंबर को 60 लाख, 11 अक्तूबर को 70 लाख, 29 अक्तूबर को 80 लाख, 20 नवंबर को 90 लाख के पार हो गए। देश में 19 दिसंबर को ये मामले एक करोड़ के पार और चार मई को दो करोड़ के पार चले गए।

❐ **रिकवरी दर 93.08 फीसदी-** केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में कोरोना से ठीक होने की दर (रिकवरी रेट) में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि इस समय देश में रिकवरी रेट 93.1 फीसदी है। उन्होंने कहा कि ऐसे जिलों की संख्या में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है जहां रोजाना औसतन सौ नए मामले सामने आ रहे हैं। इस समय देश के 257 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना वायरस संक्रमण के रोज 100 से अधिक नए मामले सामने आ रहे हैं। संक्रमण की दैनिक दर 6.38 फीसदी दर्ज की गई। लगातार 11 दिनों से यह दर 10 प्रतिशत से कम दर्ज की गई है। साप्ताहिक संक्रमण दर घटकर 7.27 प्रतिशत हो गई है। देश में इलाजरत मरीजों की संख्या 16,35,993 हो गई जो कुल संक्रमण का 5.73 प्रतिशत है जबकि कोविड-19 से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 93.08 प्रतिशत है।

❐ **मृत्यु दर दो फीसदी से भी नीचे-** पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के कुल 77,420 मामले घटे हैं। स्वस्थ होने वालों की संख्या संक्रमित होने वालों की तुलना में लगातार 22वें दिन ज्यादा रही। अब तक स्वस्थ हुए लोगों की कुल संख्या 2,65,97,655 हो गई है, जबकि संक्रमण से मृत्यु दर 1.19 प्रतिशत है।

❐ **तेजी कम हो रहे हैं सक्रिय मामले-** मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 2713 मरीजों की मौत के बाद मृतक संख्या 3,40,702 हो गई है जबकि इलाज करा रहे लोगों की संख्या लगातार चौथे दिन 20 लाख से कम दर्ज की गई। मंत्रालय ने बताया कि बृहस्पतिवार को कुल 20,75,428 जांच की गई जिसके बाद देश में कोविड-19 के लिए हुई जांच की कुल संख्या 35,74,33,846 हो गई है।

❐ **पहली खुराक देने में अमेरिका को पीछे किया-** उधर नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) डॉ. वीके पॉल ने कहा कि ऑवर वर्ल्ड इन डाटा के अनुसार भारत में ऐसे लोगों की संख्या 17.2 करोड़ है, जिन्हें टीके की कम से कम एक खुराक दी जा चुकी है। हमने अपने देश में वैक्सीन की पहली खुराक पाने वाले लोगों की संख्या के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। डॉ. वीके पॉल ने कहा कि कोवाक्सीन और जायडस के टीकों को पहले ही बच्चों पर परीक्षण हो रहा है। हमें करीब 25 करोड़ टीकों की जरूरत होगी। कोवाक्सीन के लिए आपातकालीन उपयोग सूची में देरी पर डॉ. पॉल ने कहा कि हम भारत बायोटेक और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के साथ काम कर रहे हैं। डाटा साझा किया जा रहा है, हम चाहते हैं कि यह मील का पत्थर जल्द ही हासिल कर लिया जाए। हम इस ओर लगातार काम कर रहे हैं।

तीसरी लहर में बच्चों के लिए भी होगा फाइजर का टीका

नई दिल्ली (आरएनएस)। भारत सरकार की ओर से क्षतिपूर्ति सुरक्षा और पूरक परीक्षण से छूट दिये जाने के संकेत के बाद फाइजर और मॉडेर्ना की वैक्सीन के देश में आने का रास्ता साफ हो गया है। फाइजर के टीके आने से भारत को कोरोना की तीसरे लहर के खिलाफ जंग में काफी मदद मिल सकती है, क्योंकि फाइजर का टीका बच्चों के लिए भी होगा। एम्स के डायरेक्टर डॉ. रणदीप गुलेरिया ने कहा कि फाइजर और मॉडर्ना को क्षतिपूर्ति सुरक्षा देने से न केवल वयस्कों बल्कि बच्चों के लिए भी कोविड-19 टीकाकरण को बढ़ावा मिलेगा। गुलेरिया ने कहा कि ऐसा पहले भी किया गया है जब सरकार ने उन सभी टीकों को आपातकालीन मंजूरी दी थी, जिन्हें यूएस, यूके या यूरोपीय संघ और डब्ल्यूएचओ की एजेंसियों द्वारा मंजूरी दी गई थी। उसके आधार पर इन एजेंसियों से मंजूरी के साथ टीकों के लिए आपातकालीन मंजूरी पहले ही वास्तविक रूप से दी जा चुकी है और क्षतिपूर्ति का मुद्दा भी हल होता दिख रहा है।

इसलिए मुझे लगता है कि हमारे पास जल्द ही बच्चों और वयस्कों के लिए फाइजर वैक्सीन आने वाली है। बता दें कि कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए फाइजर की भूमिक अहम हो सकती है, क्योंकि कई डेटा के विश्लेषणों और वैज्ञानिक शोधों से यह आशंका जाहिर की गई है कि तीसरी लहर में बच्चे कोरोना के टारगेट हो सकते हैं। यही वजह है कि अब तीसरी लहर से बच्चों को बचाने की तैयारियां तेज हो रही हैं। इधर प्रमुख घरेलू टीका विनिर्माता कंपनी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कहा कि उसे भी कोविड टीका दायित्व के तहत क्षतिपूर्ति सुरक्षा मिलनी चाहिये।

सुप्रीम कोर्ट में आसाराम की अंतरिम जमानत याचिका खारिज

» आयुर्वेदिक इलाज के लिए भेजने की याचिका पर होगी सुनवाई

नई दिल्ली (आरएनएस)। दुष्कर्म के मामले में जेल में सजा काट रहे आसाराम बापू को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। हालांकि, शीर्ष कोर्ट ने इस बात का परीक्षण करने का फैसला लिया है क्या दुष्कर्म मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम बापू को राजस्थान के आयुर्वेदिक अस्पताल में इलाज के लिए शिफ्ट किया जा सकता है या नहीं?

कोरोना से पीड़ित हो चुके आसाराम ने आग्रह किया है कि उन्हें एलोपैथिक दवाओं के सहारे न रखा जाए। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार तक राज्य को इस संबंध में पक्ष रखने के लिए कहा है और अब मंगलवार को इस मामले की सुनवाई होगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में राज्य सरकार से जवाब मांगा है।

उच्च न्यायालय ने आसाराम को उनकी पंसद के चिकित्सा केंद्र में उपचार कराने के लिए सजा निलंबन की याचिका खारिज कर दी थी। उल्लेखनीय है कि आसाराम को यौन उत्पीड़न के मामलों में उम्र कैद की सजा समेत विविध अवधि के कारावास की कई सजा मिली है। याचिका पर सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा, ''हम चिकित्सा के विशेषज्ञ नहीं हैं।'' पीठ ने कहा कि वह सजा निलंबन पर विचार नहीं करेगी बल्कि आसाराम को उत्तराखंड के एक केंद्र में उपचार कराने की इजाजत देने के बाबत राज्य का रूख जानना चाहेगी। न्यायालय ने कहा, ''हम सरकार से कहेंगे कि वह उन्हें वहां (केंद्र में) भर्ती कराए। आसाराम के वकील सिद्धार्थ लूथरा ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि सीटी स्कैन से पता चलता है कि आसाराम के फेफड़ों को 38 फीसीदी नुकसान हुआ है और उन्हें वायरल निमोनिया है। साथ ही उन्हें गैस्ट्रो-आंत्र रोगों से पीड़ित और ऑक्सीजन की समस्या है। बता दें कि आसाराम बापू साल 2013 से जोधपुर की सेंट्रल जेल में सजा काट रहा है।

सीबीआई अधिकारियों के लिए निर्धारित हुआ ड्रेस कोड

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के नए डायरेक्टर सुबोध कुमार जायसवाल ने पद संभालते ही ड्यूटी के दौरान अधिकारियों अथवा स्टाफ के लिए ड्रेस कोड निर्धारित कर दिया है। सीबीआई के नए चीफ ने आदेश दिया है कि एजेंसी के प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी कार्यालय में उचित फॉर्मल पोशाक पहनेंगे। उन्होंने कहा कि दफ्तर में जींस, टी-शर्ट्स और स्पोर्ट्स जूते नहीं चलेंगे।

जायसवाल के जारी आदेश के अनुसार पुरुष अधिकारी फॉर्मल शर्ट-पैंट और फॉर्मल जूते ही पहनेंगे। इतना ही नहीं, उन्हें प्रोपर शेविंग (दाढ़ी बनवाकर) के साथ ही ऑफिस भी आना होगा। वहीं, ड्यूटी के दौरान महिला अफसरों या स्टाफ को सिर्फ साड़ी, सूट और फॉर्मल शर्ट पहनने को कहा गया है। सीबीआई डायरेक्टर सुबोध कुमार जायसवाल की मंजूरी के साथ उप निदेशक (प्रशासन) अनूप टी मैथ्यू द्वारा जारी एक आदेश में यह कहा गया है। आदेश में स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि ऑफिस में जींस, टी-शर्ट, स्पोर्ट्स शूज, चप्पल पहनकर आने की अनुमति नहीं है। आदेश में देश भर में सीबीआई की सभी शाखाओं के प्रमुखों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि इन दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए।

सीबीआई के सूत्रों की माने तो यह एक संतुलित आदेश है, क्योंकि एक पेशेवर जांच एजेंसी के रूप में प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी को फॉर्मल कपड़े पहनने की जरूरत होती है। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में लोगों ने कैजुअल जैसे जींस और टी-शर्ट पहनना शुरू कर दिया और किसी ने इसे रोका नहीं, विशेष रूप से मंत्रालय के कर्मचारियों ने। सीबीआई अधिकारियों को कम से कम एक फॉर्मल कॉलर वाली शर्ट, ट्राउजर और जूते पहनने की जरूरत है। गौरतलब है कि सुबोध जायसवाल ने पिछले बुधवार को सीबीआई के 33वें निदेशक के रूप में पदभार संभाला था। उनके नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एक उच्चस्तरीय पैनल ने मुहर लगाई थी। घटनाक्रम से परिचित लोगों ने कहा कि 1985 बैच के आईपीएस अधिकारी सुबोध कुमार जायसवाल द्वारा आने वाले दिनों में प्रमुख जांच एजेंसी के भीतर कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक परिवर्तन करने की संभावना है ताकि इसकी दक्षता में सुधार हो और जनता में इसकी छवि को और बेहतर किया जा सके।

सितंबर-अक्टूर तक आएगी कोरोना की तीसरी लहर

» दूसरी लहर से हम अच्छी तरह लड़े : नीति आयोग

नई दिल्ली (आरएनएस)। नीति आयोग के सदस्य वीके सारस्वत ने कहा कि भारत ने कोविड-19 की दूसरी लहर का सामना काफी अच्छी तरह से किया और इसलिए संक्रमण के नए मामलों की संख्या में काफी कमी आई है। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि तीसरी लहर से निपटने के लिए भी तैयारियां पूरी होनी चाहिए, जिससे युवा आबादी के अधिक प्रभावित होने की आशंका है।

सारस्वत ने कहा कि भारत के महामारी विशेषज्ञों ने बहुत स्पष्ट संकेत दिए हैं कि कोविड-19 की तीसरी लहर अपरिहार्य है और इसके सितंबर-अक्तूबर से शुरू होने की आशंका है। इसलिए देश को अधिक से अधिक लोगों का टीकाकरण करना चाहिए। सारस्वत ने कहा कि मुझे लगता है कि हमने काफी हद तक अच्छा किया है। हमने कोविड-19 की दूसरी लहर का अच्छी तरह सामना किया और यह उसी का परिणाम है कि संक्रमण के नए मामले काफी कम हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी गतिविधियों की मदद, ऑक्सीजन बैंक बनाना, बड़ी संख्या में ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए उद्योग स्थापित कर, हम महामारी से निपटने में कामयाब रहे। रेलवे, हवाईअड्डों, सैन्य बल का इस्तेमाल तरल ऑक्सीजन को ले जाने के लिए किया जा रहा है। देश में पहले चार लाख से अधिक रोजाना मामले सामने आ रहे थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में संक्रमण के नए मामलों की संख्या गिर कर लगभग 1.3 लाख पर आ गई है।

कर्नाटक में 14 जून तक बढ़ा लॉकडाउन, 500 करोड़ रुपये के पैकेज का ऐलान

बेंगलुरू (आरएनएस)। कर्नाटक के ग्रामीण इलाकों में भी कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के बीच मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा ने लॉकडाउन को और एक सप्ताह के लिए बढ़ाने की घोषणा की। लॉकडाउन 14 जून की सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। उन्होंने फिल्म और टीवी उद्योग के कार्यकर्ताओं, मछली पकड़ने वाले समुदाय, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, बुनकरों और पूजा स्थलों में काम करने वाले लोगों सहित विभिन्न समूहों के लिए कुल 500 करोड़ रुपये के दूसरे राहत पैकेज की भी घोषणा की।

यह राहत पैकेज उन लोगों के लिए राहत के रूप में 1,111.82 करोड़ रुपये के वित्तीय पैकेज के अतिरिक्त है, जिनकी आजीविका सिर्फ एक पखवाड़े पहले घोषित किए गए लॉकडाउन से प्रभावित हुई है।

कर्नाटक की कोविड तकनीकी सलाहकार समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि चल रहे लॉकडाउन प्रतिबंध में तभी ढील दी जा सकती है जब सकारात्मकता दर पांच प्रतिशत से कम हो जाए और राज्यभर में मामलों की संख्या 5,000 से कम हो जाए।

यहां मंत्रियों के साथ अनौपचारिक बैठक के बाद, येदियुरप्पा ने संवाददाताओं से कहा कि चल रहे तालाबंदी को एक और सप्ताह के लिए बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि गांवों में कोविड के कारण स्थिति सबसे खराब है।

राज्य में पहले 24 मई से 7 जून तक कड़े प्रतिबंधों की घोषणा की थी। उन्होंने कहा, हालांकि संक्रमण नियंत्रण में आ गया है, लेकिन बीमारी का प्रकोप अभी भी जारी है। इसलिए, हमने विशेषज्ञों की सिफारिश के बाद एक सप्ताह के लिए, 14 जून की सुबह तक प्रतिबंध विस्तार करने का फैसला किया है।

सदी की सबसे बड़ी चुनौती कोरोना महामारी : नरेन्द्र मोदी

नई दिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएसआईआर की सालाना बैठक में कोरोना महामारी को सदी की सबसे बड़ी चुनौती करार दिया। वहीं कोरोना संकट काल में स्वदेशी वैज्ञानिकों को आभार जताते हुए कहा कि एक साल में कोरोना किट बनाकर भारत को आत्मनिर्भर बनाया गया।

पीएम मोदी ने पीएम नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वैज्ञानिकों की तारीफ की है। उन्होंने कोरोना की सदी की सबसे बड़ी चुनौती बताया और कहा कि इतिहास गवाह है कि जब भी जब-जब मानवता पर कोई संकट आया है तो विज्ञान ने बेहतर भविष्य के रास्ते तैयार कर दिए हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि बीती शताब्दी का अनुभव है कि जब पहले कोई खोज दुनिया के दूसरे देशों में होती थी तो भारत को उसके लिए कई-कई साल का इंतजार करना पड़ता था। लेकिन आज हमारे देश के वैज्ञानिक दूसरे देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, उतनी ही तेज गति से काम कर रहे हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने एक साल में ही स्वदेशी कोरोना वैक्सीन तैयार कर दी। कोरोना की बीमारी से निपटने के लिए नई-नई दवाएं खोजीं। ऑक्सीजन के उत्पादन में इजाफे के लिए प्रयास किए। पीएम ने कहा कि हमारी इस संस्था ने देश को कितनी ही प्रतिभाएं दी हैं, कितने ही वैज्ञानिक दिए हैं। शांतिस्वरूप भटनागर जैसे महान वैज्ञानिक ने इस संस्था को नेतृत्व दिया है। उन्होंने कहा कि आज भारत सस्टेनेबल डेवलेपमेंट और क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। आज हम सॉफ्टवेयर से लेकर सैटेलाइट्स तक, दूसरे देशों के विकास को भी गति दे रहे हैं, दुनिया के विकास में प्रमुख इंजन की भूमिका निभा रहे हैं।

❐ **आम लोगों को भी वैज्ञानिक रिसर्च से जोड़ना होगा-** ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति आपके रिसर्च के बारे में जान सकें और चाहता है तो फिर जुड़ भी सके। इसके लिए आपको निरंतर जोर देना होगा। इससे आपके काम और प्रोडक्ट्स को भी मदद मिलेगी। साथियों आज देश आजादी के 75 साल पूरे करने वाला है। हमें इस बात को ध्यान में रखते हुए स्पष्ट संकल्पों और निश्चित दिशा में रोडमैप के साथ आगे बढ़ना होगा। कोरोना के इस संकट ने भले ही रफ्तार धीमी की है, लेकिन आज भी हमारा संकल्प आत्मनिर्भर और सशक्त भारत है।

❐ **विदेशी नागरिकों की वीजा अवधि 31 अगस्त तक बढ़ाई-** गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि कोविड-19 महामारी के कारण भारत में फंसे विदेशी नागरिकों के वीजा की अवधि 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। यह राहत उन्हें निशुल्क दी गई है। इन नागरिकों को बढ़ी हुई वीजा अवधि के लिए न तो कोई आवेदन करना होगा और न ही किसी तरह की पेनल्टी या शुल्क अदा करना होंगे।